International Journal of Advanced Research in Education and TechnologY(IJARETY)

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 4, Issue 1, January 2017 ||

सांप्रदायिकता और भारतीय राजनीति महात्मा गांधी और नेहरू

Dr. Ganpat Ram Suthar

Associate Professor, SBK Govt. PG College, Jaisalmer, Rajasthan, India

सार

इस वर्ष 30 जनवरी को उन लोगों के हाथों महात्मा गांधी की हत्या के ठीक 75 वर्ष हो जाएंगे जो उनके अहिंसा के संदेश और समन्वित भारत की उग्र रक्षा के विरोधी थे। लेखों और वीडियो की एक श्रृंखला में, द वायर गांधी की हत्या का जायजा लेता है, और स्वतंत्र भारत के पहले आतंकवादी कृत्य के पीछे की ताकतों और विचारों की गहराई से पड़ताल करता है। हाल के वर्षों में गांधी, उनके विचारों, भावना और संदेश को मारने का एक और प्रयास देखा गया है। हम आशा करते हैं कि राष्ट्रपिता की विरासत के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, इसके माध्यम से भारत आज कहां खड़ा है और इसका भविष्य क्या है, इसे उजागर करने में मदद मिलेगी।

परिचय

भारत के विभाजन की त्रासदी के छह महीने से भी कम समय बाद, 30 जनवरी, 1948 को, नवोदित राज्य में एक और त्रासदी हुई। यदि विभाजन को बड़े पैमाने पर उपनिवेशवाद द्वारा समर्थित मुस्लिम सांप्रदायिकता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो हिंदू सांप्रदायिकता "महानतम जीवित हिंदू" की हत्या की जिम्मेदारी लेती है। नेहरू के शब्दों में:

"सांप्रदायिकता के परिणामस्वरूप न केवल देश का विभाजन हुआ, जिसने लोगों के दिलों में एक गहरा घाव दिया, जिसे भरने में बहुत समय लगेगा, अगर यह कभी भर गया, बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या भी हुई।"

गांधी जी की हत्या एक पूर्व नियोजित कृत्य था। नवंबर 1947 में, बिहार के सीपीआई किसान नेता कार्यानंद शर्मा ने चेतावनी दी थी कि हिंदू राज की मांग "बहुत बुरी थी और इसके पीछे गांधीजी और पंडितजी की हत्या की साजिश थी". 20 जनवरी, 1948 को उनके जीवन पर किए गए असफल प्रयास की वास्तविक प्रकृति को गांधीजी ने स्वयं समझा था। जब एक सहकर्मी को आश्चर्य हुआ कि क्या बम विस्फोट आकस्मिक था, तो उन्होंने उत्तर दिया: "मूर्ख; क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसके पीछे एक भयानक और व्यापक षडयंत्र है?"[1,2,3]

1937 में हिंदू महासभा में अपने अध्यक्षीय भाषण मेंहिंदुत्व की अवधारणा के निर्माता, द्वि-राष्ट्र सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले पहले व्यक्ति और महात्मा की हत्या की साजिश के आयोजक वीडी सावरकर ने घोषणा की: "आज भारत को एक एकतावादी और समरूप राष्ट्र नहीं माना जा सकता है, लेकिन इसके विपरीत भारत में मुख्य रूप से दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुस्लिम।" वह "हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय दुश्मनी" का उल्लेख करते हैं। जिस अनुभाग में उपरोक्त कथन दिए गए हैं उसका शीर्षक है, 'वैसे तो भारत में दो विरोधी राष्ट्र एक साथ रहते हैं।' भारत एक राष्ट्र नहीं है बल्कि यह उस राज्य का नाम है जिसमें ये दोनों राष्ट्र मौजूद हैं।

15 अगस्त 1947 को दो राष्ट्र-राज्यों का जन्म हुआ। उनमें से एक, पाकिस्तान, को सावरकर की राष्ट्र की परिभाषा के अनुरूप कहा जा सकता है, लेकिन वह, जिसका वह हिस्सा था, भारत, हठपूर्वक इस अनुरूप आने से इनकार कर रहा था। ऐसा लगता था कि सबसे बड़ी बाधा स्वयं महात्मा थे। उसे हटाना पड़ा. उनके जीवित रहते न तो हिंदू राष्ट्र और न ही अखंड भारत वास्तविकता बन सका।

इस बात पर आम सहमति है कि सावरकर के नेतृत्व वाली हिंदू महासभा की एक उग्र शाखा ही गांधी की हत्या के पीछे थी. जनवरी 1948 में, जब गांधी की हत्या हुई, सावरकर को साजिश के पीछे के मास्टरमाइंड के रूप में गिरफ्तार किया गया था। आपराधिक कानून के एक तकनीकी बिंदु, अनुमोदक की गवाही को पुष्ट करने के लिए सबूतों की कमी के कारण अंततः उन्हें गांधी हत्या के मुकदमे से बरी कर दिया गया। एक अच्छे आपराधिक वकील होने के नाते, सरदार पटेल व्यक्तिगत रूप से सावरकर के अपराध के प्रति आश्वस्त थे, अन्यथा वे उन पर मुकदमा चलाने के लिए सहमत नहीं होते। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को खरी-खरी सुनाई:

"यह सीधे तौर पर सावरकर के अधीन हिंदू महासभा की एक कट्टर शाखा थी जिसने साजिश रची और इसे अंजाम दिया।"

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 4, Issue 1, January 2017 ||

जब 1965 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीवन लाल कपूर के नेतृत्व में गठित जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, तो वह निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा::

"ये सभी तथ्य एक साथ लेने पर सावरकर और उनके समूह द्वारा हत्या की साजिश के अलावा किसी भी सिद्धांत को नष्ट करने वाले थे।"

कपूर आयोग के पास बहुत सारे सबूत थे जो ट्रायल जज के पास उपलब्ध नहीं थे। सावरकर के दो करीबी सहयोगियों, एपी कसार और जीवी दामले, जिन्होंने मुकदमे में गवाही नहीं दी थी, ने कपूर आयोग के समक्ष बात की, अब जब सावरकर मर चुके थे, और अनुमोदक के बयानों की पुष्टि की। यदि उन्होंने मुकदमे में गवाही दी होती तो सावरकर दोषी साबित हो गए होते. किसी भी मामले में, गोडसे और आप्टे के राजनीतिक गुरु के रूप में, जिनकी बरी केवल तकनीकी कानूनी आधार पर हुई थी, वह जनता की नजर में इस कृत्य के लिए राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार और नैतिक रूप से दोषी ठहराए गए थे।

नाथूराम गोडसे ने अपने मुकदमे में कहा कि केवल वह और आप्टे ही साजिश में शामिल थे, हिंदू महासभा, अकेले आरएसएस का इससे कोई लेना-देना नहीं था। यह बिल्कुल झूठ था. गोडसे का सब कुछ आरएसएस और हिंदू महासभा से था। जहां तक सावरकर के साथ संबंध की बात है , आप्टे और गोडसे सावरकर के अनुचर थे। सावरकर ने उनके अखबार अग्रणी , जिसे बाद में हिंदू राष्ट्र नाम दिया गया, को वित्तपोषित किया । वे उनके राजनीतिक दौरों में उनके साथ यात्रा करते थे। गोडसे मुख्य आयोजक थे और आप्टे सावरकरवादी संगठन, हिंद राष्ट्र दल के सचिव थे, जिसकी स्थापना 1942 में पूना में महासभा की गुप्त गतिविधियों को चलाने के लिए एक स्वयंसेवी संगठन के रूप में की गई थी।. वे निष्पादक थे और वह गांधी की हत्या की साजिश के पीछे प्रेरक प्रतिभा और मास्टरमाइंड थे।

गोडसे के आरएसएस से संबंधों की पुष्टि उसके भाई ने भी की थी। हालाँकि, आरएसएस ने अपने सामान्य दोगले तरीके से इस बात पर जोर दिया है कि वह उनसे जुड़े नहीं थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने 1993 में एक साक्षात्कार में कहा था: "नाथूराम गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कटु आलोचक थे। उनका आरोप था कि आरएसएस ने हिंदुओं को नपुंसक बना दिया है. हमारा गोडसे से कोई लेना-देना नहीं है. कांग्रेस की आदत है कि जब उसे कुछ और नहीं मिलता तो वह हमारे खिलाफ इस आरोप को फिर से उछाल देती है।"उनके भाई और साथी साजिशकर्ता, गोपाल गोडसे ने आडवाणी के दावे का जोरदार विरोध किया और जोर देकर कहा कि नाथूराम ने कभी आरएसएस नहीं छोड़ा था, लेकिन गोलवलकर और आरएसएस को बचाने के लिए मुकदमे में अपने बयान में ऐसा कहा था।.

जैसा कि डीआर गोयल ने बताया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आरएसएस का अध्ययन और संघर्ष करते हुए बिताया है, यह खुलासा कर रहा है कि फांसी पर चढ़ने से पहले उन्होंने जो प्रार्थना की वह नई संस्कृत आरएसएस प्रार्थना थी, जिसने 1940 में पुरानी हिंदी मराठी प्रार्थना की जगह ले ली थी।. यदि वह अब आरएसएस में नहीं थे, जैसा कि उन्होंने दावा किया था, तो उन्हें नई प्रार्थना कैसे पता चली और उन्होंने इसे अपने जीवन के ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, इसके अंत की दहलीज पर क्यों पढ़ा?

आरएसएस और हिंदू महासभा को यह दिखाने में परेशानी हो रही थी कि उनका एक-दूसरे से, या गांधी की हत्या के पीछे के साजिशकर्ताओं से, वास्तव में पूरी तरह से राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। यह सर्वविदित है कि दोनों संगठनों के अलग-अलग अस्तित्व का मतलब केवल एक ही उद्देश्य के लिए श्रम का विभाजन था। आरएसएस और हिंदू महासभा के सदस्यों ने एक साथ काम किया, पहले ने वैचारिक आधार बनाया, दूसरे ने औपचारिक राजनीतिक दल बनाया। आरएसएस और हिंदू महासभा के बीच यह ओवरलैप कपूर आयोग की रिपोर्ट से स्पष्ट है। जब 8 अगस्त, 1947 को गृह सचिव द्वारा डीआइजी, सीआईडी, बॉम्बे और कमिश्नर, पुलिस, बॉम्बे को आरएसएस और हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करने के लिए कहा गया, तो पूना पुलिस ने पूना के महासभा नेताओं की एक सूची भेजी; इसने आरएसएस के लिए एक अलग सूची तैयार नहीं की। इससे दोनों के बीच अंतर करने में कठिनाई का पता चलता है। कपूर आयोग आगे कहता है कि "यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि आरएसएस के कई सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य थे।" मोरारजी देसाई ने जीवन लाल कपूर आयोग के समक्ष गवाही दी कि "उस समय हिंदू महासभा और आरएसएस एक साथ काम कर रहे थे"। आरके खादिलकर, पुरषोत्तमदास त्रिकमदास और एनएस गुर्टू, बंबई के सभी गवाहों ने आयोग के समक्ष अपनी गवाही में आरएसएस और हिंदू महासभा का एक साथ उल्लेख किया।

17 सितंबर, 1947 को आरएसएस की गतिविधियों पर एक रिपोर्ट में कहा गया:

"…इसके अधिकांश प्रमुख आयोजक और कार्यकर्ता या तो हिंदू महासभा के सदस्य हैं या हिंदू महासभा विचारधारा के प्रायोजक हैं। …चूंकि यह हिंदू महासभा से जुड़ा था इसलिए इसकी नीति काफी हद तक सभा की विचारधारा से प्रभावित थी।

हालिया शोध आरएसएस और हिंदू महासभा के बीच इस घनिष्ठ संबंध की पुष्टि करता है, जिससे दोनों संगठनों द्वारा प्रचारित मिथक का पर्दाफाश हो जाता है कि उनका एक-दूसरे से कोई लेना-देना नहीं है:

IJARETY

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 4, Issue 1, January 2017 ||

"आम तौर पर स्वीकृत राय के अनुसार - उग्र हिंदू धर्म के संगठनों द्वारा समर्थित - आरएसएस और हिंदू महासभा कभी भी विशेष रूप से करीब नहीं रहे हैं, और, सावरकर की अध्यक्षता के दौरान, उन्होंने अपने संबंध तोड़ दिए। हालाँकि, वास्तविकता कुछ और ही प्रतीत होती है। वास्तव में, उपलब्ध दस्तावेज़ न केवल यह दर्शाते हैं कि ऐसा विभाजन कभी नहीं हुआ, बल्कि यह भी कि दोनों संगठनों के बीच हमेशा घनिष्ठ संबंध रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हेडगेवार 1926 से 1931 तक हिंदू महासभा के सचिव रहे थे [कैसोलरी के पाठ का नोट 13]। ऐसा लगता है कि आरएसएस ने हिंदू महासभा को समर्थन प्रदान किया है, जैसा कि इस तथ्य से पता चलता है कि आरएसएस उग्रवादियों के समूह सावरकर की रिहाई का जश्न मनाने के लिए आयोजित सार्वजनिक बैठकों में इकट्ठा होते थे [कैसोलरी के पाठ का नोट 14] ।"

खुफिया रिपोर्टें भी आरएसएस और महासभा के बीच सांठगांठ की गवाही देती हैं. उदाहरण के लिए, 18 मई, 1942 को आरएसएस पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के नोट में कहा गया था:

"संघ की नीति काफी हद तक हिंदू महासभा के साथ उसके जुड़ाव से प्रभावित है। वास्तव में संघ हिंदू महासभा के साथ कितनी निकटता से जुड़ा हुआ है, यह ज्ञात नहीं है, क्योंकि किसी भी संगठन के नेताओं द्वारा इसके संघ का कोई सार्वजनिक संदर्भ कभी नहीं दिया गया है। हालाँकि, यह करीब है, यह उस सम्मान से स्पष्ट है जिसके साथ वीडी सावरकर और डॉ. बीएस मुंजे जैसे हिंदू महासभा के नेताओं के साथ संघ व्यवहार करता है और जिस अधिकार के साथ वे संघ के बारे में सार्वजनिक घोषणाएँ करते हैं।

साम्प्रदायिकों के दोहरे व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण गांधी हत्या मुकदमे के दौरान सावरकर का आचरण है। वह यह आभास देने के लिए इतने उत्सुक थे कि उनका इस साजिश से कोई लेना-देना नहीं है, उन्होंने नाथूराम गोडसे और अन्य आरोपियों से अदालत में सार्वजनिक रूप से और साथ ही जेल में अकेले में बात करने से भी इनकार कर दिया। परचुरे और गोपाल गोडसे के बचाव पक्ष के वकील पीएल इनामदार ने अपने संस्मरणों में दर्ज किया है कि:

"पूरे मुकदमे के दौरान, मैंने कभी भी सावरकर को नाथूराम की ओर भी अपना सिर घुमाते नहीं देखा, जो उनके पास बैठता था, वास्तव में, उनके बगल में, उनसे बात करना तो दूर की बात है··· सावरकर वहां पूरी तरह से मौन में बैठे रहे। कटघरे में खड़े अपने सह-अभियुक्तों को बिल्कुल अनुशासित तरीके से नजरअंदाज करना...[4,5,6]

नाथूराम के साथ मेरी विभिन्न बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि वह इससे बहुत आहत हुए थे - तात्याराव (सावरकर) ने लाल किला मुकदमे के सभी दिनों के दौरान या तो अदालत में या लाल किला जेल में उनके साथ प्रदर्शनात्मक गैर-संबद्धता की गणना की। कैसे नाथूराम कोठरियों की एकांत परिधि में तात्याराव के हाथ के स्पर्श, सहानुभूति के एक शब्द या कम से कम करुणा की दृष्टि के लिए तरसता था। शिमला उच्च न्यायालय में उनसे मेरी आखिरी मुलाकात के दौरान भी नाथूराम ने इस संबंध में अपनी आहत भावनाओं का जिक्र किया था।"

इनामदार यह भी उद्धृत करते हैं कि कैसे सावरकर ने महात्मा के प्रति अपनी प्रशंसा के संबंध में अदालत में एक महान कार्य किया:

"सावरकर ने अपने मामले के बचाव में एक लिखित बयान तैयार किया था··· और उन्होंने अदालत में बयान को एक वक्ता के सभी हथकंडों के साथ पढ़ा, जिसमें उन्होंने स्वतंत्र भारत सरकार द्वारा महात्माजी की हत्या का आरोप लगाए जाने पर अपने भाग्य पर अफसोस जताया था, जबकि उन्होंने इसकी प्रशंसा की थी। और महात्माजी के व्यक्तित्व की इतनी ईमानदारी से और इतनी बार प्रशंसा की। सावरकर ने अपने भाषण के इस भाग को पढ़ते समय वास्तव में अदालत में अपने गाल पोंछे थे।"

यह देखते हुए कि सावरकर की गांधी की तीखी आलोचना सर्वविदित थी, खासकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनने के बाद, यह काफी उल्लेखनीय है कि उन्हें खुद को गांधी के प्रशंसक के रूप में पेश करने के लिए ऐसा पाखंडी प्रयास करना चाहिए था। लेकिन माफ़ी मांगने, वचन देने और अच्छे व्यवहार के आश्वासन के उनके पहले के इतिहास को देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं है. गांधी की हत्या के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारी के तीन सप्ताह के भीतर, उन्होंने आर्थर रोड जेल के पुलिस आयुक्त को एक अभ्यावेदन दिया, जिसमें उन्होंने "सरकार को एक वचन देने की इच्छा व्यक्त की कि ... [वह] किसी भी सांप्रदायिक या राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने से परहेज करेंगे।" यदि मुझे उस शर्त पर रिहा किया जाता है तो सरकार द्वारा अपेक्षित किसी भी अवधि के लिए सार्वजनिक गतिविधि।"

नेहरू को आरएसएस द्वारा बेगुनाही के विरोध में नहीं लिया गया। उसने कहा:

"इन लोगों के हाथों पर महात्मा गांधी का खून लगा है और पवित्र अस्वीकरण और अलगाव का अब कोई मतलब नहीं है।"

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 4, Issue 1, January 2017 ||

वह स्पष्ट था:

"यह हिंदू राष्ट्र की मांग के समर्थकों में से एक था जिसने सबसे महान जीवित हिंदू की हत्या कर दी।"

हिंदू महासभा के अस्वीकरण के बारे में, पटेल ने 6 मई, 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखा:

"…हम इस तथ्य से अपनी आँखें बंद नहीं कर सकते कि महासभा के सदस्यों की एक बड़ी संख्या ने इस त्रासदी पर खुशी मनाई और मिठाइयाँ बाँटीं। इस मामले पर देश के तमाम हिस्सों से हमारे पास विश्वसनीय रिपोर्टें आई हैं. इसके अलावा, उग्र सांप्रदायिकता, जिसका प्रचार कुछ महीने पहले तक महासभा के कई प्रवक्ताओं द्वारा किया गया था, जिनमें महंत दिगबिजय नाथ, प्रो. राम सिंह और देशपांडे जैसे लोग भी शामिल थे, को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा माना जा सकता है। यही बात आरएसएस पर भी लागू होगी, सैन्य या अर्ध-सैन्य तर्ज पर गुप्त रूप से चलाए जाने वाले संगठन में अतिरिक्त खतरा निहित है।"

बॉम्बे के मुख्यमंत्री बीजी खेर ने पटेल को महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति के बारे में बताया:

"कांग्रेस और महात्मा के खिलाफ नफरत का माहौल हिंदू महासभा ने बनाना चाहा, जिसकी परिणति कुछ महाराष्ट्रियों के हाथों महात्मा गांधी की हत्या के रूप में हुई।"

हत्या की तैयारी

हालाँकि वास्तविक साजिश सीधे सावरकर के नियंत्रण में एक छोटे समूह द्वारा रची गई हो सकती है, लेकिन अंतिम विश्लेषण में यह 1947 के संघर्षग्रस्त दिनों में नफरत और कड़वाहट का माहौल था जिसने इस तरह के जघन्य अपराध को संभव बनाया। पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस के प्रति, गांधी के प्रति शत्रुता को बढ़ावा दिया गया था, लेकिन अब निंदा की भाषा में काफी गुणात्मक और ध्यान देने योग्य वृद्धि हुई है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि विभाजन के साथ हुए दंगों, पलायन और नरसंहारों से बना सांप्रदायिक माहौल हिंदू सांप्रदायिकता के विकास के लिए बेहद अनुकूल था। उग्र मुस्लिम विरोधी प्रचार, दंगों को भड़काना और आयोजित करना, एक हिंदू राज्य की मांग और सरकार को उखाड़ फेंकने और राष्ट्रीय नेताओं को फांसी देने का आह्वान जनवरी 1948 में गांधी की हत्या से ठीक पहले चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया।
हिंदू महासभा ने आज़ादी के आगमन का जश्न नहीं मनाया और 15 अगस्त, 1947 को शोक दिवस घोषित किया। इसने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और भगवा झंडे को ही पूजनीय एकमात्र ध्वज माना। सत्तारूढ़ दल के रूप में कांग्रेस पर राज्य को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए बार-बार दबाव डाला गया। ऐसी मांग का उठना ही इस समय तक हिंदू सांप्रदायिक ताकतों की ताकत का सूचक था। 7-8 जून, 1947 को हिंदू महासभा की अखिल भारतीय समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव इस प्रकार था:

"समिति हिंदुओं को चेतावनी देना अपना कर्तव्य समझती है और जब तक वे भविष्य में अधिक सावधान और सतर्क नहीं होंगे और एक वास्तविक और शक्तिशाली हिंदू राज्य के निर्माण के लिए तत्काल और प्रभावी कदम नहीं उठाएंगे , न केवल नई प्रस्तावित व्यवस्थाओं के तहत उनके हित असुरक्षित होंगे बल्कि इसके अलावा वे भारत का जो कुछ बचा है उसे भी खो सकते हैं।"

आज़ादी के बाद, हिंदू सांप्रदायिक समूह कांग्रेस को प्रभावित करने की बजाय सीधे "संगठित" सांप्रदायिक "हिंसा" भड़काने लगे।. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, दिल्ली उनके संचालन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। वे सितंबर 1947 के दंगों के पीछे थे। नेहरू ने पटेल को लिखा:

"जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, हमें सरकार को पलटने, या कम से कम इसके वर्तमान चरित्र को तोड़ने के लिए कुछ सिख और हिंदू फासीवादी तत्वों के एक बहुत ही निश्चित और सुसंगठित प्रयास का सामना करना पड़ा है। यह सांप्रदायिक अशांति से कहीं अधिक कुछ है। इनमें से कई लोग हद दर्जे तक क्रूर और संवेदनहीन रहे हैं। उन्होंने शुद्ध आतंकवादियों के रूप में काम किया है।' निस्संदेह, जहां तक जनता की राय का सवाल है, वे ऐसा केवल अनुकूल माहौल में ही सफलता के साथ कर सकते थे। उनके पास वह माहौल था. इन गिरोहों को अभी तक तोड़ा नहीं जा सका है, हालाँकि उन पर कुछ किया गया है, और वे अभी भी बड़ी शरारत करने में सक्षम हैं।[7,8,9]

हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय नेताओं पर हिंदुओं के हितों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने धमकी दी कि नेहरू, पटेल और आज़ाद को फाँसी दे दी जाएगी और 'गांधी मुर्दाबाद (गांधी की मौत)' महासभा की बैठकों में एक आम नारा बन जाएगा। 18 दिसंबर, 1947 के दिल्ली पुलिस एब्सट्रैक्ट ऑफ़ इंटेलिजेंस ने आरएसएस की एक वार्षिक रैली की रिपोर्ट दी,

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 4, Issue 1, January 2017 ||

जिसमें 50,000 स्वयंसेवकों ने भाग लिया था, जहाँ गोलवलकर ने सरकार के रवैये को "अभारतीय और शैतानी" बताया था। 8 दिसंबर, 1947 को 2,500 कार्यकर्ताओं की एक बैठक में गोलवलकर ने कहा:

"संघ पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा और अगर कोई उनके रास्ते में आएगा तो वे उसे भी ख़त्म कर देंगे। "कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वह नेहरू सरकार होगी, या कोई अन्य सरकार।" उन्होंने कहा, भारत उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा, उनके [आरएसएस] के पास ऐसे साधन हैं जिससे उनके विरोधियों को तुरंत चुप कराया जा सकता है।"

27 जनवरी, 1948 को दिल्ली में एक बैठक में महासभा के नेता महंत दिग्विजयनाथ ने सभा से महात्मा गांधी और अन्य हिंदू विरोधी तत्वों को पाकिस्तान भेजने का आह्वान किया। गोडसे के अखबार अग्रणी ने लिखा:

"क्या सत्ता के नशे में अंधा सुल्तान हिंदू लोगों के खून को एक पाई के बराबर नहीं समझता है, ताकि यह बनिया जो अपने समुदाय (मतलब महात्मा गांधी) के लिए गद्दार है, कई नदियों के बहने के बावजूद भी नए उपाय करे।" इन राक्षसी हमलावरों की खून की प्यास को संतुष्ट करना।"

विचार-विमर्श

यदि वह अपना आत्मसम्मान बरकरार रखना चाहता है तो उसे आत्महत्या करने की सलाह दी गई; यदि नहीं, तो उन्हें भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए अलविदा कह देना चाहिए।

9 जुलाई 1947 के हिंदू राष्ट्र ने उपदेश दिया :

"मातृभूमि का हनन किया गया, गिद्धों ने उसके मांस के टुकड़े नोच डाले, खुली सड़कों पर हिंदू (साहित्यिक आर्य) महिलाओं की पवित्रता का उल्लंघन किया गया, सब कुछ नष्ट हो गया और कांग्रेसी नपुंसकों की बड़ी बंदूकें बलात्कार होते देखती रहीं उनकी पत्नियाँ तुम पर गुर्राने लगी हैं। इसे कोई कब तक सहन कर सकता है? और यदि यह पीड़ा आदत का विषय बन जाएगी, तो जीवन भर के परिवहन में इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है?

आम तौर पर हत्या के लिए आजीवन कारावास की सज़ा होती है, यह हत्या के लिए जितना स्पष्ट सार्वजनिक प्रोत्साहन हो सकता था उतना स्पष्ट था।

जहां तक गांधी का सवाल है, सांप्रदायिकतावादियों के लिए आखिरी तिनका भारतीय क्षेत्र में अचल संपत्ति के पाकिस्तान के हिस्से के मुआवजे के रूप में भारत सरकार द्वारा उन्हें दिए जाने वाले 55 करोड़ रुपये के तत्काल भुगतान की पाकिस्तान की मांग का समर्थन करना था। भारत सरकार झिझक रही थी क्योंकि वह कश्मीर में पाकिस्तान के साथ सशस्त्र संघर्ष में लगी हुई थी और इस धन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सकता था। अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान किया जाना चाहिए, इस बात पर जोर देने के लिए गांधी 13 जनवरी, 1948 को उपवास पर चले गए। भारतीय सरकार को भुगतान करना पड़ा, लेकिन इससे तुरंत ही हिंदू संप्रदायवादियों को हमला करने के लिए आवश्यक गोला-बारूद मिल गया। मुसलमानों के तुष्टिकरण का रोना और भी तेज़ हो गया। 20 जनवरी को मदन लाल पाहवा द्वारा गांधी के जीवन पर एक प्रयास किया गया, उसके बाद 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे की सफल हड़ताल हुई।

हिंदुत्व कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या के लिए इस्तेमाल की गई पिस्तौल की तस्वीर। श्रेय: जीवन लाल कपूर जांच आयोग की रिपोर्ट, 1969।

गोडसे ने अपने कृत्य की व्याख्या इस प्रकार की:

"वर्षों की बढ़ती उत्तेजना, जो उनके अंतिम मुस्लिम समर्थक उपवास में परिणत हुई, ने आखिरकार मुझे इस निष्कर्ष पर पहुँचाया कि गांधीजी के अस्तित्व को तुरंत समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने गांधीजी की सहमति से देश को, जिसे हम पूज्य देवता मानते हैं, विभाजित और छिन्न-भिन्न कर दिया, तो मेरा मन भयंकर क्रोध के विचारों से भर गया। मुझे लगा कि गांधीजी की अनुपस्थिति में भारतीय राजनीति निश्चित रूप से व्यावहारिक होगी, प्रतिकार करने में सक्षम होगी और सशस्त्र बलों के साथ शक्तिशाली होगी। मैंने जो कार्य किया वह पूरी तरह मानवता की भलाई के लिए किया है। मैं कहता हूं कि मेरी गोलियां उस व्यक्ति पर चलाई गईं, जिसकी नीति और कार्रवाई ने लाखों हिंदुओं को बर्बादी और विनाश दिया था।"

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 4, Issue 1, January 2017 ||

यह और बात है कि वास्तव में गांधी की हत्या का असर उल्टा हुआ. इसने उन लोगों को भयभीत कर दिया जो हिंदू सांप्रदायिक सोच के प्रति सहानुभूति रखते थे। गांधी के एक करीबी सहयोगी ने लिखा:

"महीनों तक पूरे भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक छेड़छाड़ से सुरक्षित थे। आरएसएस ने महात्मा को नष्ट करके देश को वह झटका दिया जिसकी उसे जरूरत थी। जो लोग क्रोधपूर्वक उनकी आलोचना कर रहे थे, उन्हें अब अपने अदूरदर्शी क्रोध के दुखद परिणाम देखने को मिले। वे जानते थे कि वह सही था।"

भारतीय राज्य की प्रकृति को ख़तरा

गांधी की हत्या ने नेहरू को इस बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ा कि हिंदू राष्ट्र के समर्थक सत्ता पर कब्ज़ा करने की योजना बना रहे थे, इससे भी कम नहीं: "ऐसा प्रतीत होता है कि एक जानबूझकर तख्तापलट की योजना बनाई गई थी जिसमें कई लोगों की हत्या और सामान्य अव्यवस्था को बढ़ावा देना शामिल था।" संबंधित विशेष समूह (आरएसएस) को सत्ता पर कब्ज़ा करने में सक्षम बनाना । ऐसा प्रतीत होता है कि यह साजिश काफी व्यापक थी, जो कुछ राज्यों तक फैल गई।"

4 फरवरी, 1948 की सरकारी विज्ञप्ति में आरएसएस को गैरकानूनी घोषित करते हुए कहा गया:

"यह पाया गया है कि देश के कई हिस्सों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्यक्तिगत सदस्यों ने आगजनी, डकैती, डकैती और हत्या सहित हिंसा के कृत्यों में लिप्त रहे हैं और अवैध हथियार और गोला-बारूद एकत्र किया है। उन्हें लोगों को आतंकवादी तरीकों का सहारा लेने, आग्नेयास्त्र इकट्ठा करने, सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा करने और पुलिस और सेना को अपने अधीन करने के लिए उकसाने वाले पर्चे प्रसारित करते हुए पाया गया है।[10,11,12]

गांधी ने 1947-48 में गोलवलकर के उन प्रयासों को मानने से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्हें यह समझाने की कोशिश की गई थी कि वे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए थे, मुसलमानों को मारने के लिए नहीं।. जब बैठक में मौजूद एक गांधीवादी कार्यकर्ता ने एनडब्ल्यूएफपी के वाह में शरणार्थी शिविर में आरएसएस द्वारा किए गए अच्छे काम की प्रशंसा की, तो गांधी ने टिप्पणी की, "लेकिन यह मत भूलो कि हिटलर के नाजी और मुसोलिनी के तहत फासीवादी भी ऐसे ही थे।"

पटेल ने मुखर्जी को यह बताया,

"आरएसएस की गतिविधियां सरकार और राज्य के अस्तित्व के लिए स्पष्ट खतरा हैं।"

इसका एहसास नेहरू को पहले ही हो गया था. 7 दिसंबर, 1947 को मुख्यमंत्रियों को लिखे गए उनके पाक्षिक पत्र में आरएसएस द्वारा उत्पन्न खतरे की प्रकृति के बारे में विस्तार से बताया गया था:

"आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो एक निजी सेना की प्रकृति का है और जो निश्चित रूप से सबसे सख्त नाजी तर्ज पर आगे बढ़ रहा है।"

नेहरू ने फासीवादी चरित्र प्राप्त कर रहे सांप्रदायिकों से लड़ने के लिए "खुफिया सेवाओं को विकसित करने की आवश्यकता पर" मुख्यमंत्रियों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। "देश में इस समय कई खतरनाक प्रवृत्तियाँ और चलन हैं जिन्हें मोटे तौर पर फासीवादी कहा जा सकता है। वे न केवल मुस्लिम हैं बल्कि हिंदू और सिख भी हैं। हमें इस बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. दिल्ली में समस्या मुख्यतः समय पर जानकारी की कमी के कारण थी।"

उन्होंने आरएसएस की धमकी को इतनी गंभीरता से लिया कि उन्होंने 7 दिसंबर, 1947 को मुख्यमंत्रियों को एक विशेष पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कोई शब्द नहीं कहे:

"हमारे पास यह दिखाने के लिए बहुत सारे सबूत हैं कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो एक निजी सेना की प्रकृति में है और जो निश्चित रूप से सख्त नाजी लाइनों पर आगे बढ़ रहा है, यहां तक कि संगठन की तकनीक का पालन भी कर रहा है। नाज़ी पार्टी ने जर्मनी को बर्बाद कर दिया और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर इन प्रवृत्तियों को भारत में फैलने और बढ़ने दिया गया, तो वे भारत को भारी नुकसान पहुँचाएँगे।

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 4, Issue 1, January 2017 ||

उन्होंने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि इस बीमारी ने उनके कुछ साथियों को भी प्रभावित किया है: "दुर्भाग्य से, कई कांग्रेसी, बिना सोचे-समझे, विचार और व्यवहार के फासीवादी और नाज़ी तरीकों के इस विकास की ओर आकर्षित हो गए हैं।"

उन्होंने चेतावनी दी कि हमें इन दावों से भ्रमित नहीं होना चाहिए कि आरएसएस एक राजनीतिक संगठन नहीं है: "उनके नेताओं द्वारा खुले तौर पर कहा गया है कि आरएसएस एक राजनीतिक निकाय नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी नीति और कार्यक्रम राजनीतिक हैं। , घोर सांप्रदायिक और हिंसक गतिविधियों पर आधारित।"

हिंदू दक्षिणपंथी एजेंडे पर नेहरू के दृढ़ विश्वास ने उन्हें, सरदार पटेल के पूर्ण समर्थन से, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने और उसके 25,000 कार्यकर्ताओं को सलाखों के पीछे डालने में सक्षम बनाया। उन्होंने मुख्यमंत्रियों को लिखे अपने पत्र में प्रतिबंध का बचाव करते हुए आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या उन्हें पहले ही अधिक सख्त होना चाहिए था। "शायद हम इन...तत्वों...से निपटने में बहुत उदार रहे हैं। कोई आधा-अधूरा उपाय नहीं हो सकता।" "मैं नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखता हूं और रहा हूं, लेकिन लोकतंत्र की बात करना बेतुका है जब इसके आधार को आतंकवादी गतिविधियों द्वारा चुनौती दी जाती है; उन लोगों को नागरिक स्वतंत्रता देना भी उतना ही बेतुका है जो हत्या और हिंसा द्वारा सत्ता पर कब्ज़ा करना चाहते हैं... हम समूहों और व्यक्तियों की कुछ स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करने के लिए कार्रवाई करने के लिए मजबूर हैं ताकि आम तौर पर लोगों को सभी स्वतंत्रता से वंचित न किया जाए।

उन्होंने आगे कहा: "देश में एक मजबूत राय है, जिसके प्रति मेरी सहानुभूति है, कि कोई भी राजनीतिक संगठन या यूं कहें कि कोई भी संगठन किसी विशेष धार्मिक समूह तक सीमित नहीं है और जिसका लक्ष्य राजनीतिक लक्ष्य है; कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए...बेशक, मैं किसी भी वैध राजनीतिक गतिविधि को दबाना नहीं चाहता। लेकिन जैसा कि हम अनुभव से जानते हैं, एक धार्मिक समूह के साथ राजनीतिक गतिविधि का संयोजन खतरनाक है। यहां तक कि वह प्रेस पर लगे प्रतिबंधों का भी सामना करने को तैयार थे, जो उस व्यक्ति के लिए विशेष रूप से कठिन था जिसने जीवन भर नागरिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया हो। उद्धृत करने के लिए: एक "गैरजिम्मेदार प्रेस... जो नफरत, सांप्रदायिक कटुता और हिंसा का पंथ फैलाता है...उसे समाप्त किया जाना चाहिए। ऐसे कागजातों से निपटने की हमारी कुछ प्रक्रियाएँ धीमी हैं। उन्हें तेज़ करना होगा।"

वास्तव में, गांधी की हत्या के बाद की अवधि में, नेहरू आरएसएस की लगातार निंदा करते रहे। उन्होंने मुख्यमंत्रियों को बार-बार चेतावनी दी कि वे अपनी सतर्कता में ढिलाई न बरतें। उदाहरण के लिए, अगस्त 1948 में, उन्होंने चेतावनी दी थी कि प्रतिबंध के बावजूद, "भारत के कई हिस्सों से हमारे पास रिपोर्टें आई हैं कि आरएसएस की गतिविधियाँ फिर से बढ़ रही हैं। आरएसएस का तरीका अक्सर धीरे बोलने का होता है लेकिन उनकी पूरी विचारधारा और गतिविधि अलग है और उस विचारधारा के विपरीत है जिसने हम पर इतने लंबे समय तक शासन किया है। इसलिए, जब तक हम सरकार हैं हम इस गलत विचारधारा के प्रोत्साहन और प्रसार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे आशा है कि प्रांतीय सरकारें इस संबंध में सचेत हैं और किसी भी रूप में सांप्रदायिक सिद्धांतों के प्रसार की अनुमति नहीं देंगी।" उन्होंने उन्हें संगठन द्वारा अपनाए गए नए रूपों के प्रति भी सचेत किया: "आरएसएस अब विभिन्न रूपों में कार्य कर रहा है, यहां तक कि नागरिक स्वतंत्रता संघ या जन अधिकार सभा के रूप में भी।"

गौरतलब है कि नेहरू को आरएसएस को दोगला कहने में कोई झिझक नहीं थी। गांधीजी की हत्या के बाद उन्होंने अपने पाक्षिक पत्र में लिखा था: "हमें याद रखना चाहिए कि हमारा विरोध करने वाले लोग पूरी तरह से बेईमान हैं। वे कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। मुझे कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों से शोक संदेश मिले हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे इस साजिश में शामिल थे।"एक साल बाद, उन्होंने फिर दोहराया, "यह याद रखना चाहिए कि आरएसएस ने हमेशा कुछ कहा है और कुछ और किया है। उन्होंने खुद को एक सामाजिक संगठन कहा है और फिर भी उन्होंने राजनीतिक स्तर पर सक्रिय और हिंसक तरीके से काम किया है।

नेहरू सरकारी सेवाओं में घुसपैठ के आरएसएस के तरीके से भी पूरी तरह परिचित थे और वे जानते थे कि यह बहुत खतरनाक है। "यह सर्वविदित है कि प्रयास किए गए हैं, और सभी प्रकार के सरकारी स्थानों, सेवाओं आदि में इन षड्यंत्रकारियों की कोशिकाओं को स्थापित करने में कुछ सफलता मिली है। हमें इन्हें शुद्ध करना होगा और अपने प्रशासन और सेवाओं को शुद्ध करना होगा।"उन्होंने मुख्यमंत्रियों से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया कि "...सरकार या सरकारी अधिकारियों को, चाहे वह केंद्र में हो या प्रांत में, हिंदू महासभा या किसी अन्य निकाय के साथ कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जो स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक है, चाहे वह कोई भी रूप धारण कर ले।" .

सांप्रदायिक ताकतों द्वारा उत्पन्न खतरे की गंभीरता के बारे में पहले प्रधान मंत्री का दृढ़ विश्वास इतना था कि आजादी के पहले ढाई वर्षों के दौरान मुख्यमंत्रियों को लिखे गए एक भी पाक्षिक पत्र को ढूंढना मुश्किल है, जिसमें उन्होंने इस पर प्रकाश नहीं डाला हो। मुद्दा और निरंतर सतर्कता और कार्रवाई का आग्रह करें.[13,14,15]

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 4, Issue 1, January 2017 ||

इसके अलावा, उन्होंने इस विषय पर विशेष पत्र भी लिखे। मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए मैं इनमें से कुछ अंश नीचे दे रहा हूं:

17 फ़रवरी 1948 को:

"मुझे विश्वास है कि आप सांप्रदायिकता को उसके सभी पहलुओं में जड़ से ख़त्म करने के अपने प्रयासों में ढील नहीं देंगे। सांप्रदायिकता के खिलाफ जनमत की ताकत के कारण, इनमें से कई सांप्रदायिक निकायों ने चुप रहने का फैसला किया, लेकिन वे अभी भी वहीं हैं और हम उनके बारे में भूलने का जोखिम नहीं उठा सकते।

1 मई, 1948 को:

"कई स्रोतों से रिपोर्टें मुझ तक पहुंची हैं कि सांप्रदायिक माहौल फिर से तनावपूर्ण हो रहा है, और विशेष रूप से आरएसएस से जुड़े लोग··· फिर से मुखर और प्रदर्शनकारी हो रहे हैं···। आरएसएस के कई लोग जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था, कुछ समय के लिए जेल में रखा गया था और फिर बाद में रिहा कर दिया गया था, उनके द्वारा दिए गए आश्वासनों के बावजूद वे फिर से इन गतिविधियों में भाग ले रहे हैं।

2 मई, 1948 को:

"वास्तविक जोखिम जिससे सावधान रहना होगा, वह हैदराबाद में विकास के परिणामस्वरूप भारत के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक परेशानी की संभावना है···। यह बेहद जरूरी है कि आरएसएस और उनके जैसे लोगों को खुद को संगठित करने और अपने तरीके से काम करने का कोई मौका न दिया जाए। ... आपकी सरकार को इन सांप्रदायिक तत्वों पर सतर्क नजर रखने दें और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ फिर से कदम उठाने दें जिन्हें खतरनाक माना जा सकता है। हमें झपकी लेते हुए नहीं पकड़ा जाना चाहिए और हम आत्मसंतुष्ट होने का जोखिम नहीं उठा सकते।

तीन दिन बाद, 5 मई, 1948 को:

"हमने हाल ही में सांप्रदायिक आंदोलनों की पुनरावृत्ति देखी है। पुराना आरएसएस विभिन्न रूपों में फिर से अपना सिर उठा रहा है...मुझे विश्वास है कि आपका प्रांत इस विकास की अनुमति नहीं देगा। मैं आपका विशेष ध्यान संविधान सभा द्वारा पारित सांप्रदायिक संगठनों के संबंध में प्रस्ताव की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। हमने कहा है कि हम किसी भी ऐसे सांप्रदायिक संगठन को मान्यता नहीं देंगे या प्रोत्साहित नहीं करेंगे जिसका राजनीतिक उद्देश्य हो। मुझे उम्मीद है कि आपकी सरकार इस नीति का पालन करेगी।"

पंद्रह दिन बाद, 20 मई, 1948 को:

"मैंने पहले भी आपका ध्यान भारत के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक भावना की पुनरावृत्ति की ओर आकर्षित किया है। आरएसएस फिर से अपना सिर उठा रहा है और पूर्वी पंजाब में ऐसे कई तत्व हैं जो परेशानी की ओर बढ़ रहे हैं। इन प्रवृत्तियों को फिर से मजबूत होने देना हमारे लिए असुरक्षित और मूर्खतापूर्ण है... अगले कुछ महीने कठिन हो सकते हैं और हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते।"

हिंदू महासभा, जिसने प्रतिबंध का सामना करने के बजाय गांधी की हत्या के बाद खुद को भंग कर लिया था, ने 8 अगस्त, 1948 को अपनी कार्य समिति की बैठक की और राजनीतिक गतिविधि फिर से शुरू करने का संकल्प लिया। प्रधान मंत्री ने तुरंत मुख्यमंत्रियों को लिखा: "आपने देखा होगा कि हिंदू महासभा फिर से राजनीति में आने का इरादा रखती है। यह एक अवांछनीय कदम है और इस पर सावधानीपूर्वक नजर रखी जानी चाहिए।" 11 अगस्त, 1948 को प्रांतीय सरकारों को प्रामाणिक धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों में लगे सांप्रदायिक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने की भारत सरकार की सलाह की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा, "सरकार या सरकारी अधिकारियों को... हिंदू महासभा या किसी अन्य निकाय के साथ व्यवहार करना जो स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक है, चाहे वह कोई भी वेश धारण कर ले।"

परिणाम

गांधी अपने 77वें जन्मदिन पर जवाहरलाल नेहरू से बात करते हुए। नई दिल्ली। भारत।

नवंबर 1948 में, उन्होंने एक बैठक के लिए आरएसएस प्रमुख गोलवलकर के लिखित अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और उन्हें बताया कि आरएसएस की गतिविधियों पर सरकार के पास उपलब्ध जानकारी उनके दावों से भिन्न है। "ऐसा प्रतीत होता है कि घोषित उद्देश्यों

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 4, Issue 1, January 2017 ||

का वास्तविक उद्देश्यों और आरएसएस से जुड़े लोगों द्वारा की जा रही गतिविधियों से बहुत कम लेना-देना है... हमारी जानकारी के अनुसार, गतिविधियाँ राष्ट्र-विरोधी और अक्सर विध्वंसक और हिंसक हैं।"

19 दिसंबर, 1948 को, कांग्रेस के जयपुर सत्र में नेहरू द्वारा तैयार सांप्रदायिक प्रश्न पर एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें "सांप्रदायिकता की भावना को समाप्त करने" का आह्वान किया गया और सांप्रदायिकता को बढ़ावा न देने या इसका दुरुपयोग न करने का दृढ़ संकल्प घोषित किया गया। धर्म एक राजनीतिक हथियार के रूप में"

जब जुलाई 1949 में आरएसएस पर से प्रतिबंध हटा दिया गया, जब उन्होंने लिखित आश्वासन दिया कि उनका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं होगा, लेकिन वे एक सांस्कृतिक संगठन होंगे, नेहरू ने फिर से अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि नागरिक स्वतंत्रता का पालन करने का मतलब यह है कि आप अनिश्चित काल तक ऐसा नहीं कर सकते। दमनकारी शक्तियों का प्रयोग करें, इसका मतलब यह नहीं था कि उनका मानना था कि बाघ ने अपने स्थान बदल लिये हैं। उद्धरण के लिए:

"जैसा कि आप जानते हैं, आरएसएस पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है…। इसका मतलब यह नहीं है कि हम आरएसएस आंदोलन की प्रामाणिकता के बारे में आश्वस्त हैं... नागरिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में हमारी सामान्य छूट का मतलब निश्चित रूप से व्यक्ति या राज्य के खिलाफ हिंसा से निपटने में थोड़ी सी भी छूट नहीं होगी, चाहे वह कहीं भी हो और किसी भी रूप में हो।[16,17]

कुछ दिनों बाद, उन्होंने फिर चेतावनी दी कि वे एक फासीवादी संस्था बने हुए हैं:

"…आरएसएस फिर से अपनी कुछ गतिविधियाँ फिर से शुरू कर रहा है…। आरएसएस की पूरी मानसिकता फासीवादी मानसिकता है. इसलिए, उनकी गतिविधियों पर बहुत बारीकी से नजर रखनी होगी।"

जनता का फैसला

यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि भारत, इसके लोग और इसके प्रधान मंत्री 1946 से 1950 के वर्षों में कठिन समय से गुजरे थे। सांप्रदायिक नरसंहार में लगभग 500,000 लोग मारे गए थे और लगभग 60 लाख शरणार्थी भारत में आ गए थे।. राष्ट्रपिता को बेरहमी से ले जाया गया. यह युवा राज्य तूफान का सामना कर सका, यह उसके सौभाग्य के कारण था कि उसके पास स्वतंत्रता के संघर्ष की ज्वाला में असाधारण रूप से सक्षम और प्रतिबद्ध नेतृत्व था।

एक बार जब गांधी जी चले गए, तो उनमें से वह नेहरू ही थे जो दूसरों को ऐतिहासिक क्षण का सार समझाने में नेतृत्व प्रदान करने में बाकियों से ऊपर थे, कि यह स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को बचाने, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के निर्माण की लड़ाई थी। और समाज. जैसा कि मैंने नेहरू के कागजात के व्यापक संदर्भों के साथ दिखाने की कोशिश की है, इस मुद्दे पर उनकी अटूट स्पष्टता महत्वपूर्ण थी जब कई अन्य लोग कम से कम कभी-कभी संदेह से घिरे थे। नेहरू स्वयं अक्सर निराश रहते थे, और निराशा के कगार पर थे, लेकिन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत पर दृढ़ता से टिके रहने की परम आवश्यकता के बारे में कभी संदेह नहीं करते थे। उन्होंने लोगों में अपने बुनियादी विश्वास को कभी नहीं छोड़ा और पहले आम चुनाव में आगे बढ़े। वह वास्तव में इस बात से नाखुश थे कि मतदाता सूची तैयार करने में कठिनाइयों के कारण देरी हुई।

नेहरू ने चुनाव अभियान को साम्प्रदायिकता के विरुद्ध अभियान में बदल दिया। उन्होंने लगभग 40,000 किलोमीटर की यात्रा की और अनुमानित 35 मिलियन लोगों या भारत की आबादी के दसवें हिस्से को संबोधित किया। नतीजा यह हुआ कि सांप्रदायिक दलों, हिंदू महासभा, नवगठित जनसंघ और राम राज्य परिषद ने 489 के सदन में केवल 10 लोकसभा सीटें जीतीं, और उन्हें छह प्रतिशत से भी कम वोट मिले। हाल ही में संपन्न चुनावों पर टिप्पणी करते हुए, नेहरू ने कहा:

"कांग्रेस परंपरा और ऐतिहासिक आवश्यकता के अनुसार देश की एकता, सांप्रदायिकता विरोधी और विघटनकारी प्रवृत्तियों के खिलाफ लड़ी। यह सच है कि इसमें बुराइयाँ आ गई थीं और यहाँ तक कि सांप्रदायिकता के कुछ तत्व भी इसके भीतर देखे जा सकते थे... हालाँकि, चुनावों में यह एकता के पक्ष में और सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ खड़ी थी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उसे इस संबंध में सफलता मिली और सांप्रदायिक पार्टियों ने उसके खिलाफ खराब प्रदर्शन किया... इन चुनावों के दौरान सांप्रदायिकता के प्रति कांग्रेस के जोरदार विरोध ने ही कांग्रेस के विकास को रोका है।"[18,19]

निष्कर्ष

इस प्रकार साम्प्रदायिकता का ज्वार, जो देश को डुबाने की धमकी दे रहा था, को भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व के अत्यंत कठिन प्रयास से पीछे धकेल दिया गया। इसमें राज्य की पूरी ताकत लग गई, जिसमें जहां आवश्यक हो वहां बल का प्रयोग और दमनकारी कानून, उचित

नीतियां, नेहरू-लियाकत समझौते जैसी कूटनीतिक पहल, एक शक्तिशाली वैचारिक अभियान के साथ मिला, जिसने राष्ट्रीय भावना को जगाकर दिल और दिमाग को प्रभावित किया। इसे संभव बनाने के लिए प्रतीकों और मानवीय मूल्यों और बहुत कुछ। लगभग एक दशक तक सांप्रदायिक ताकतें बैकफुट पर रहीं। 1957 के चुनावों में भी उनका प्रदर्शन ख़राब रहा।[20]

संदर्भ

1. "गांधी" ।14 जनवरी 2015 को वेबैक मशीन पर संग्रहीत रैंडम हाउस वेबस्टर्स अनब्रिज्ड डिक्शनरी ।
2. ^ मैकएलिस्टर, पाम (1982)। जीवन के जाल को फिर से बुनना: नारीवाद और अहिंसा । न्यू सोसाइटी पब्लिशर्स। पी। 194. आईएसबीएन 978-0-86571-017-7. 31 अगस्त 2013 को पुनःप्राप्त .उद्धरण: "प्यार से, आपका, बापू (आपने अपने करीबी दोस्तों द्वारा इस्तेमाल किए गए स्नेह शब्द के साथ समापन किया, वह शब्द जो आपने सभी आंदोलन नेताओं के साथ इस्तेमाल किया था, जिसका मोटे तौर पर अर्थ 'पापा' है।) 1940 में लिखा गया एक और पत्र भी इसी तरह की कोमलता और देखभाल दिखाता है .
3. ^ एक, डायना एल. (2003)। एनकाउंटरिंग गॉड: ए स्पिरिचुअल जर्नी फ्रॉम बोज़मैन टू बनारस। बीकन प्रेस. पी। 210. आईएसबीएन 978-0-8070-7301-8. 31 अगस्त 2013 को पुनःप्राप्त .उद्धरण: "...उनकी भतीजी मनु, जो अन्य लोगों की तरह इस अमर गांधी को 'बापू' कहती थी, जिसका अर्थ 'पिता' नहीं, बल्कि परिचित, 'डैडी' था।' ' (पृ. 210)
4. ^ गांधी, मोहनदास के. (2009)। एक आत्मकथा: सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी । फ्लोटिंग प्रेस. पी। 21. आईएसबीएन 978-1-77541-405-6. 29 मार्च 2015 को मूल से संग्रहीत । 29 मार्च 2015 को पुनःप्राप्त .
5. ^ गांगुली, देबजानी; डॉकर, जॉन, एड. (2008), रीथिंकिंग गांधी एंड अहिंसक रिलेशनलिटी: ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स , रूटलेज , पीपी. 4-, आईएसबीएन 978-1-134-07431-0, 21 जुलाई 2015 को मूल से संग्रहीत , 21 जुलाई 2016 को पुनः प्राप्तउद्धरण: "...गांधी को एक मिश्रित महानगरीय व्यक्ति के रूप में चिह्नित किया गया है, जिन्होंने बीसवीं सदी में उपनिवेशवाद-विरोधी राष्ट्रवादी राजनीति को ऐसे तरीकों से बदल दिया, जो न तो स्वदेशी और न ही पश्चिमी भारतीय राष्ट्रवादी कर सके।"
6. ^ भारत से पहले गांधी . पुरानी किताबें. 16 मार्च 2015. पीपी. 19-21. आईएसबीएन 978-0-385-53230-3.
7. ^ गुहा 2015 पीपी. 19-21
8. ^ मिश्रा, अमलेंदु (2004)। पहचान और धर्म: भारत में इस्लाम विरोध की नींव । ऋषि प्रकाशन। पी। 67. आईएसबीएन 978-0-7619-3227-7. गांधी, राजमोहन (2006)। मोहनदास: गांधी द्वारा एक आदमी, उसके लोगों और एक साम्राज्य की सच्ची कहानी । पेंगुइन बुक्स इंडिया। पी। 5. आईएसबीएन 978-0-14-310411-7. मल्होत्रा, एसएल (2001)। महात्मा के वकील: एमके गांधी का जीवन, कार्य और परिवर्तन । गहन एवं गहन प्रकाशन। पी। 5. आईएसबीएन 978-81-7629-293-1. 29 मार्च 2015 को मूल से संग्रहीत । 29 मार्च 2015 को पुनःप्राप्त .
9. ^ गुहा 2015 , पृ. 21
10. ^ गुहा 2015 , पृ. 512
11. "Indian National Congress". inc.in. मूल से 5 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2 जनवरी 2016.
12. ↑ "Nation pays tribute to Pandit Jawaharlal Nehru on his 124th birth anniversary". मूल से 1 जुलाई 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 28 February 2015.
13. ↑ Moraes 2008, पृ॰ 4.
14. ↑ Zakaria, Rafiq A Study of Nehru, Times of India Press, 1960, p. 22
15. ↑ Moraes 2008.
16. ↑ Bonnie G. Smith; The Oxford Encyclopedia of Women in World History. Oxford University Press. 2008. ISBN 978-0195148909. pg 406–407.
17. ↑ हमारी विरासत, डॉ॰ राधाकृष्णन, हिन्द पॉकेट बुक्स प्रा॰लि॰, दिल्ली, संस्करण-1989, पृष्ठ-107.
18. ↑ श्याम बेनेगल निर्मित इस धारावाहिक के बारे में प्रगतिशील वसुधा के सुप्रसिद्ध 'सिनेमा विशेषांक' में कहा गया है कि 'भारत एक खोज' (1988) धारावाहिक टेलीविजन पर एक ऐसी कृति के रूप में सामने आया जिसका आज बीस साल बाद भी कोई मुकाबला नहीं है। द्रष्टव्य- हिंदी सिनेमा : बीसवीं से इक्कीसवीं सदी तक, (प्रगतिशील वसुधा का सिनेमा विशेषांक, अंक-81, अप्रैल-जून, 2009), अतिथि संपादक- प्रहलाद अग्रवाल, पुस्तक रूप में 'साहित्य भंडार, 50 चाहचंद रोड, इलाहाबाद' से प्रकाशित, पृष्ठ-383.
19. ↑ हमारी विरासत, डॉ॰ राधाकृष्णन, हिन्द पॉकेट बुक्स प्रा॰लि॰, दिल्ली, संस्करण-1989, पृष्ठ-96.
20. ↑ जवाहरलाल नेहरू वाङ्मय, खंड-5, सस्ता साहित्य मंडल, नयी दिल्ली, प्रथम संस्करण-1976, पृष्ठ-'चार'।